

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 17 जून, 2008

विषय:-

मै0 मर्क (MIRC) इलैक्ट्रॉनिक्स लि0 UNIT-2 के मैगा प्रोजेक्ट हेतु जनपद हरिद्वार की तहसील रुडकी के गाम मुण्डियाकि में कुल 2.9020 है0 भूमि कय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-319/भूमि व्यवस्था-भू0क0-VIII दिनांक 02 मई, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय मै0 मर्क (MIRC) इलैक्ट्रॉनिक्स लि0 UNIT-2 के मैगा प्रोजेक्ट हेतु उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत जनपद हरिद्वार की तहसील रुडकी के ग्राम मुण्डियाकी के खसरा सं0-399 से 401, 405 से 410 तक कुल रकबा 2.9020 है0 भूमि कय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- क्रेता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2- क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में

.....(2)

अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (वाशिंग मशीन एवं अन्य कन्ज्यूमर ड्यूरेबल उत्पादों के निर्माण) के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गई भूमि कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी एवं भूमि का कब्जा प्राप्त होने के 180 दिन के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना होगा एवं दो वर्ष के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना होगा।

7- मैगा प्रोजेक्ट के लिये प्रस्तावित ग्राम मुण्डियाकी, तहसील रुडकी, जिला हरिद्वार स्थित खसरा सं०-399 से 401, तथा 405 से 410 तक कुल रकबा 2.9020 है० भूमि भारत सरकार वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 50/2003 सेंट्रल एक्साइज दिनांक 10 जून 2003 जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत Category & C Industrial Activity in Non Industrial Area (To Be Notified along with extension) के अधीन कगांक-9 पर अधिसूचित है। जिसे अधिसूचना संख्या 27-27/2005-सी०ई० दिनांक 19 मई, 2005 के एनैक्जर-2 में Industrial Activity in Non Industrial Area के रूप में प्रतिस्थापित किया जा चुका है, में स्थापित उद्योग के पर्याप्त विस्तार अथवा नये उद्योग की स्थापना पर (नकारात्मक उद्योगों को छोड़कर) भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज का लाभ अर्हता पूर्ण करने पर अनुमन्य होगा।

8- GIDCR-2005 में औद्योगिक इकाई के भवन निर्माण के लिये दिये गये मानकों, उपबन्धों, विधियों/उपविधियों का पूर्णतः पालन करना होगा।

9— प्रस्तावित विशेष औद्योगिक आस्थान की आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी द्वारा कय अनुबन्धित है। अतः विशेष औद्योगिक आस्थान के नियोजित विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कयानुबन्धित भूमि के कय विलेख पत्र (Sale Deed) नियगतः निष्पादित कराकर GIDCR-2005 के उपबन्धों के अनुरूप (i) कृषि भू-उपयोग से औद्योगिक भू-उपयोग परिवर्तन सुनिश्चित कराना होगा और (ii) तत्पश्चात् विशेष औद्योगिक आस्थान में स्थापित होने वाली कम्पनी की प्रस्तावित इकाई का भवन मानचित्र सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना होगा।

10— विशेष औद्योगिक आस्थान के रख-रखाव, अवस्थापना सुविधाओं के विकास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का दायित्व, आस्थान के प्रवर्तक कम्पनी का होगा। कम्पनी द्वारा आस्थान में उपलब्ध करायी जाने वाली अवस्थापना सुविधाओं तथा अन्य के सम्बन्ध में सभी स्पष्ट सूचनायें उपलब्ध करायी जायेगी।

11— आस्थान को विकसित करने के लिये विभिन्न विभागों जैसे वन एवं पर्यावरण विभाग, राजस्व विभाग, अग्निनिशमन विभाग, उत्तरांचल पॉवर कॉरपोरेशन आदि से वांछित विभिन्न स्वीकृति/ अनुमति/अनुमोदन/अनापत्ति आदि जो भी वांछित औपचारिकतायें अपेक्षित होंगी, वह प्रवर्तक कम्पनी द्वारा स्वयं पूर्ण की जायेंगी।

12— कम्पनी उद्योग स्थापना से पूर्व यह अण्डरटेकिंग लिखित में देगी कि आस्थान में उद्योग स्थापना के उपरान्त 70 प्रतिशत नियमित रोजगार/सेवायोजन स्थानीय व प्रदेश के लोगो को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भूमि/भूखण्ड की कय विलेख पत्र/लीज डीड में भी इस शर्त को उल्लिखित किया जायेगा।

13— इकाई द्वारा कय की जाने वाली भूमि का उपयोग वाशिंग मशीन एवं टिकाउ उत्पादों विनिर्माण उद्योग तथा उसके वांछित आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना हेतु ही किया जायेगा।

14— विशेष औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों यथा प्रदेश की औद्योगिक निति के अन्तर्गत एसी औद्योगिक इकाईयाँ, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा हतोत्साहित किया जा रहा है अथवा जो भारत सरकार की नकारात्मक सूची में सम्मिलित है, की स्थापना औद्योगिक आस्थान में नहीं की जायेगी।

15— मैगा प्रोजेक्ट हेतु स्पॉट जोनिंग के लिये निश्चित मानको/ दिशा निर्देशों का पूर्णतः पालन किया जायेगा तथा प्रोजेक्ट में प्रस्तावित पूँजी निवेश 31 मार्च, 2010 तक पूर्ण करना होगा।

- 16- प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा। प्रश्नगत अनापत्ति मात्र भूमि क्रय व्यवस्था के सन्दर्भ में दी जा रही है। आवेदक को आवेदित भूमि का नियमानुसार अपने पक्ष में क्रय करने के उपरान्त नियमानुसार मैगा प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु विशेष औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित/विनियमित कराना होगा।
- 17- प्रश्नगत इकाई की स्थापना के संबंध में अनापत्ति मात्र भूमि क्रय व्यवस्था के संदर्भ में दी जा रही है और पैकेज के अन्तर्गत देय सुविधाओं/छूट हेतु इकाई की अर्हता स्वतः निर्धारित नहीं करती है जो इकाई की स्थापना के पश्चात आवेदन करने पर सुसंगत नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।
- 18- किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 19- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 20- नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/अनापत्तियां प्राप्त कर ली जायेंगी।
- 21- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

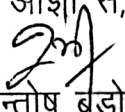
(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, देहरादून।
- 3- सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 4- सचिव, श्रम एवं सेवायोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीडा एवं प्रबंध निदेशक सिडकुल, देहरादून।

- 6- श्री राजेश राधकृष्णन, जनरल मैनेजर, ऑपरेशन एण्ड प्रोजेक्ट, गर्क इलेक्ट्रॉनिक्स
लि0, जी0-1, MIDC, मकाली केव्स रोड, अन्धेरी ईस्ट, मुम्बई।
7- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।